

सम्पादकीय

आम बजट अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को उम्मीद की किरण दिखाने वाला है। समग्र दृष्टि से परिपूर्ण वृद्धि पर केंद्रित यह एक भविष्योन्मुखी बजट है। रोजगार को बढ़ाने वाला है। फिर भी न्यायिक सुधार एवं पुलिस सुधार जैसे मुद्दों की अनदेखी रह गई। इससे व्यापार एवं जीवन की सुगमता से जुड़े सुधारों से मिलने वाले व्यापक लाभ पर आघात की आशंका दिखती है। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से वैसी ही रहीं जैसी हर साल रहती हैं। बजट का वास्तविक आकलन तभी संभव है जब उसे खांटी राजनीतिक दृष्टि के बजाय समग्रता में देखा जाए। इस लिहाज से बजट में कुछ बेदु प्रमुखता से उभरते हुए दिखेंगे। पहला तो यही कि यह बजट भविष्योन्मुखी है। सूचना दे

दैवियोगिकी, ड्रोन, एआई, नाकचेन, डिजिटल करेंसी जैसे इह उभरते चमकदार क्षेत्रों पर गोर यहीं दर्शाता है। स्वच्छ ऊर्जा भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इं-गवर्नेंस में निवेश बढ़ाने जीवन गुणवत्ता सुधरने के लाभ ही डिजिटल डिवाइड की आई भी भरेगी। संचार, निर्माण, व्यापार, वितरण नोरंजन से लेकर कृषि और तिरक्षा तंत्र में तकनीक से भाभ उठाने की योजना बनाई इह है। इंटरने शानल इन्नेशियल सेंटर को लेकर योगधर्मिता और विदेशी व्यवहारियालयों के संचालन को च प्रदान करने के फैसले भी व्यवस्था को रपतार देने में ददगार होंगे। ये कुछ ऐसे नदम हैं, जिनमें भविष्य की व्यवस्था को गढ़ने एवं उसे बाहरने की पर्याप्त क्षमताएं हैं। जट हालिया परिस्थितियों को खत्ते हुए पटरी पर लौट रही

समग्र दृष्टि से परिपूर्ण वृद्धि पर केन्द्रित यह एक भविष्योन्मुखी बजट है। रोजगार को बढ़ाने वाला

आर्थिक गतिविधियों को सहारा देता है। इसमें एमएसएमई से लेकर आतिथ्य सत्कार से जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ाने के उपाय हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। गति शक्ति मिशन पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है। इन कदमों से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी। आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी लागत घटने और इन्वेंट्री यानी भंडारण प्रबंधन में भी सुधार होगा। स्टार्ट अप्स, वै चर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के लिए सुगम की गई राह नवाचार को बढ़ाने एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों एवं सेवाओं के विकास को गति प्रदान करेगी। पूंजीगत व्यय में 35 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी कर आवंटन को 7.5 लाख करोड़ रुपये करने से सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उसका लक्ष्य तेज आर्थिक वृद्धि है। साथ ही राज्यों को भी एक लाख करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण का प्रविधान किया है। इससे निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऊंची जीडीपी वृद्धि के लिए बड़े स्तर पर निवेश भी जरूरी है। सार्वजनिक-निजी निवेश की दोहरी शक्ति में अर्थव्यवस्था को निरंतर सात से आठ प्रतिशत की सतत वृद्धि के चक्र में दाखिल कराने की क्षमता है। कुछ प्रयासों से बैंकों और निजी क्षेत्र के बहीखाते दुरुस्त हुए हैं। इससे पूंजीगत व्यय को नए सिरे से आगे बढ़ाने में प्राप्त हुई क्षमताओं के बावजूद कुछ हिचक कायम है। ऐसे में सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने से उनका हौसला जरूर बढ़ेगा। रोजगार का मुद्दा अभी बहुत चुनौतीपूर्ण है। कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, बुनियादी ढांचा और विनिर्माण रोजगार प्रदान करने वाले तीन सबसे बड़े क्षेत्र हैं। बजट में सस्ती दरों पर वित्त की व्यवस्था और किफायती मकानों के लिए आवंटन बढ़ाकर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को बड़ा सहारा दिया गया है। अकेले गति शक्ति मिशन में ही रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने गत वर्ष जो पीएलआइ योजना पेश की थी, उसने विनिर्माण क्षेत्र का कायाकल्प कर बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान किए हैं। अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र का निर्यात 300 अरब डालर के आंकड़े को पार कर जाएगा। इससे एक करोड़ से अधिक नौकरियां बनेंगी। महंगाई की चुनौती भी इस समय जीडीपी वृद्धि के लिए एक बड़ा जोखिम है। बढ़ती महंगाई आर्थिक वृद्धि

से लाभान्वित हुए एक बड़े तबके के लाभ में संधि लगा सकती है। यही कारण है कि वित्त मंत्री ने राजकोषीय अनुशासन को ले कर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ ही राजस्व व्यय के बजाय कहीं अधिक उत्पादक पूँजीगत व्यय में वृद्धि को वरीयता दी। बजट प्रस्ताव पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी दर्शाते हैं। कर प्रक्रियाओं को सुगम बनाने एवं करदाताओं में विश्वास जताने की परिपाठी भी कायम रही। जैसे रिटर्न भरने के लिए मिली दो साल की मोहलत यही बताती है कि सरकार को करदाताओं पर पूरा भरोसा है। एक ऐसे समय में जब सरकारी कमाई में तेजी दिख रही है तब मांग बढ़ाने और समाज के वंचित तबकों को सीधी राहत पहुंचाने के लिए खास उपायों के अभाव से जुड़ी आलोचना कछ हट तक

वाजिब लगती है। हालांकि इसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभी वैश्विक परिदृश्य डांगडोल है। महामारी की विदाई नहीं हुई है, देशों में राष्ट्रवाद मुखर होने के साथ ही भू-राजनीतिक तनाव भी चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए रक्षा कवच तैयार करने का विकल्प चुना। कुछ और चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी हैं। जैसे किसी अनुबंध के अमल में आने से जुड़ी विश्व के 180 से अधिक देशों की सूची में भारत 168वें स्थान पर है। भारत में किसी परियोजना को सिरे चढ़ाने में औसतन 1,200 से अधिक दिन लगते हैं और लागत मूल कि न्यायिक तंत्र, नौकरशाही और पुलिस संबंधी सुधार अब अनिवार्य हो चले हैं। उनमें मामूली बदलाव या अपर्याप्त सुधार से काम नहीं चलेगा। इन संस्थानों को संवैधानिक गारंटी के अनुरूप फिर से गढ़ना होगा। जब तक ये उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक कारोबारी एवं जीवन को सुगम बनाने के उपाय मूर्त रूप नहीं ले पाएंगे। अमृत काल में जब देश को उन्नति के उच्च पथ पर अग्रसर कर स्वतंत्रता की शताब्दी पूरी होने तक शिखर पर पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है तब बजट इन सुधारों की अनदेखी करता प्रतीत होता है।

र भी समग्रता में देखा
वित्त मंत्री ने मुश्किल
में संतुलित और
बजट पेश किया है।

राजनीति नहीं, देशहित का दूरगामी अमृत बजाए

लालत गग
सप्तकृष्ण

सशक्त एवं विकासत भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और कोरोना महामारी से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। यह कदम एक ऐसे समय उठाया गया जब राजनीतिक दृष्टि से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और उन्हें लघु आम चुनाव की भी संज्ञा दी जा रही है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। कोरोना की संकटकालीन एवं चुनौतीभरी परिस्थितियों में लोकल्याणकारी एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बल देने वाला यह बजट अभिनन्दनीय एवं सराहनीय है। यह बजट एवं उम्मादों का आकार दन का दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के भी वर्गों का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। इस बजट से भले ही करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी हो, टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था का जो नक्शा सामने आया है वह इस मायने में उम्मीद की छाँव देने वाला है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में भारी-भरकम व्यय करने की योजना बनाई उसके साकार होने से अंततः आम आदमी को ही लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अर्थव्यवस्था को गति देने का काम शहरीकरण की उन योजनाओं को आगे बढ़ाने से भी होगा जिनकी प्रावधान बजट में किया गया है। इस बजट में शहर एवं गांवों के संतुलित विकास पर बल दिया है, जो इस बजट की विशेषता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत खर्चों में 35.4 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है,

इससे राजगार में वृद्ध होगा। यह बहुत बड़ा फैसला है। वित्त मंत्री ने बजट में क्रिप्टोकरंसी पर भी निवेशकों की उलझन दूर कर दी। उन्होंने इससे हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। वित्त वर्ष 2023 में रिजर्व बैंक डिजिटल करंसी लाएगा, इसका ऐलान भी निर्मला सीतारमण ने किया। इन दोनों बातों से लगता है कि सरकार ने क्रिप्टोकरंसी को एक एसेट तो मान लिया है, लेकिन वह इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहती। यहां तक कि समृद्ध तबके को भी दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के टैक्स पर सरचार्ज घटाकर राहत दी गई है। अस्सी लाख सस्ते घरों के लिये 48 हजार करोड़ का प्रावधान करके निम्न-मध्यम आय वर्ग के लिए हाउसिंग सेक्टर में सौगात दी गई है।

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष में आधिक क्षत्र में काप उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सब स्थितियों तो बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट के माध्यम से देश व स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाएंगे। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजटों पर प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाते रहते हैं। लेकिन इस बार बजट ने कोरोना महासंकट से बिगड़ा, अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा तथा साथ राहत की सांसें दी है ताकि नया भारत—सशक्त भारत व निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया जा सके। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलवे का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों विकास के साथ-साथ किसानों गांवों और गरीबों को ज्यादा तत्त्वज्ञों दी गयी है। सच्चाया यही है कि जब तक जमीन विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी है।

आर उन उम्मादा पर यह बजट खरा उतरा है। हर बार की तरह इस बार भी शहरों के मध्यमवर्ग एवं नौकरीपेश लोगों को अवश्य निराशा हुई है। इस बार आम बजट को लेकर उत्सुकता इसलिए और अधिक थी, क्याँकि यह कोरोना महासंकट, पड़ोसी देशों के लगातार हो रहे हमलों, निरस्तेज हुए व्यापार, रोजगार, उद्यम की स्थितियों के बीच प्रस्तुत हुआ है। संभवतः इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकंक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं

सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षों के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते हैं लेकिन इस बार का बजट चुनाव होने के बावजूद राजनीति प्रेरित नहीं है। स्पष्ट है कि सरकार ने चुनावी राजनीतिक

हता क आग अथवावस्था का सशक्त करने के दूरामी लक्ष्य पर न केवल ध्यान केंद्रित किया बल्कि यह भी रेखांकित किया कि उसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक समर्थ-सक्षम देश के रूप में सामने लाना है।

गरीब तबके और ग्रामीण आबादी की बढ़ती बेचौनी को दूर करने की कोशिश इसमें स्पष्ट दिखाई देती है जो इस बजट को सकारात्मकता प्रदान करती है। इस बजट में किसानों की बढ़ती परेशानियों को दूर करने के भी सार्थक प्रयत्न हुए हैं, जिसे मेहरबानी नहीं कहा जाना चाहिए। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपी जारी रहने का उल्लेख करते हुए जिस तरह यह रेखांकित किया कि इस मद में 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वह यही बताता है कि सरकार ने उस दुष्प्रचार की हवा निकालना आवश्यक समझा जिसके तहत कुछ कथित किसान नेताओं के साथ कई विपक्षी नेता यह झूट फैलाने में लगे हैं कि यह सरकार एमएसपा खत्म करने का इसारा रखती है। इस पर हैरानी नह कि विपक्ष को बजट रास नह आया। वह सबैव इसी तरह क नकारात्मक प्रतिक्रिया से लैंगिक दिखता है और यही कारण कि जनता उसकी आलोचन पर उतना ध्यान नहीं देती जितना उसे देना चाहिए। खेतों और किसानों की दशा सुधारने सरकार की प्राथमिकता में होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा देश किसान एवं ग्रामीण आबादी का आर्थिक सुदृढ़ता और उनके क्रय शक्ति बढ़ने से ही आर्थिक महाशक्ति बन सकेगा। और तभी एक आदर्श एवं संतुलित अर्थव्यवस्था का पहिया सह तरह से धूम सकेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था संवारने की दिशा में इस बजट को मील का पत्थर कहा जा सकता है।

इस बजट में जो नया दिशाएं उद्घाटित हुई हैं और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जनसंकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहरबानी करनी होगी।

रा जनाक्रोश के घटनाक्रम के सही स्वरूप को समझने का समय

तो ऐसी अन्यान्य घटनाएं इस सिद्धांत की अवसरवादिता।
तु अभिशप्त हैं। चौरी चौरा समकालीन प्रतिक्रिया जो हुई,
यदि राष्ट्रीय फलक पर शायद उसने चौरी चौरा की

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और
स्वाधीनता के लिए भारतीयों का
भगीरथ प्रयास अंतर्निहित इतिहास ही
माने जा सकते हैं। इस संपूर्ण
घटनाक्रम का चित्रफलक इतना
व्यापक है कि वैश्विक इतिहास लेखन
में भारतीय स्वाधीनता की गाथा
सर्वाधिक लोकप्रिय है, परंतु विभिन्न
प्रकार के इतिहास लेखनों की प्रवृत्तियों
ने स्वाधीनता की गाथा की जो
पटकथा प्रस्तुत की, उसके फलस्वरूप
देश की स्वाधीनता में जिन्होंने सर्वस्व
न्यौठावर कर दिया, उन्हें और उनकी

मझना है तो जलियांवाला बाग
आना होगा। एक तथाकथित
उसंस्कृत राष्ट्र ने निहत्थे
परतीयों का कत्लेआम किया।
नाक्रोश राष्ट्रीय हुआ और
सहयोग आंदोलन को इसके
पारण आधार मिला। चौरी चौरा
ग आक्रोश जलियांवाला बाग
गे घटना का प्रत्युत्तर था, परंतु
भार्गवश घटना ने असहयोग
आंदोलन को ही समाप्त कर
दिया। विवेचना का प्रश्न है कि
ह दर्भार्गवश था या एक

घटना के इतिहास लेखन को
प्रभावित किया। बारदोली प्रस्ताव
के पूर्व ही गोरखपुर खिलाफत
कांग्रेस समिति ने चौरी चौरा
पर निंदा प्रस्ताव पारित करते
हुए घटना से स्वयं को असंबद्ध
किया। परंतु वास्तविकता यह
थी कि घटना में अधिकांशतरु
असहयोग से जुड़े हुए स्वयंसेवक
थे जो ग्रामीण अंचल पर मदिरा
और मांस के बहिष्कार को आगे
बढ़ा रहे थे। एक फरवरी 1922
को ऐसे ही एक स्वयंसेवक

भगवान अहीर की चौरी चौरा के तत्कालीन दारोगा गुप्तेश्वर सिंह के द्वारा पिटाई कर दी गई थी, क्योंकि वह बाजार में मांस की बिक्री का विरोध कर रहा था। अर्थात मूल रूप से गांधी जी के आहवान पर चौरी चौरा में यह असहयोग का एक रूप था। तीन फरवरी, 1922 तक के इस घटनाक्रम को चौरी चौरा का प्रथम समय खंड काल यानी फर्स्ट टाइम लाइन माना जा सकता है। चौरी चौरा का द्वितीय समय खंड काल यानी सेकंड टाइम लाइन चार फरवरी, 1922 से प्रारंभ माना जा सकता है, जब स्वयंसेवकों के दल ने भगवान अहीर की पिटाई के खिलाफ थाने तक जुलूस ले जाने का कार्य किया। यह सर्वमान्य है कि जुलूस के स्वयंसेवक न ही किसी को मारने की योजना से गए थे और न ही उनकी मंशा थाना को जलाने की थी। घटनाक्रम कुछ जलियांवाला बाग की तरह ही हुआ। निहत्यों पर प्रशासन द्वारा पहले लाठीचार्ज किया गया, तत्पश्चात उन पर गोलीबारी की गई। वाचिक इतिहास के तथ्यों से पता चलता है कि इस गोलीबारी में तीन स्वयंसेवक मारे गए, जिनका जिक्र सरकारी रिकार्डों में नहीं किया गया। तदुपरांत भीड़ उग्र हुई और चौरी चौरा के थाने और सिपाहियों को जलाने की घटना घटी। परंतु उग्र हुए भारतीयों ने अपने विवेक का परिचय दिया और थानाध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह की गर्भवती पत्नी को सुरक्षित जाने का मार्ग दिया। चौरी चौरा का तीसरा समय खंड काल यानी थर्ड टाइम लाइन गोरखपुर सत्र न्यायालय में दाखिल वाद से प्रारंभ माना जा सकता है, जिस समय चौरी चौरा की घटना से जुड़े जनों के साथ न ही कांग्रेस संगठन के रूप में खड़ी थी, न ही अन्य कोई। यह आश्चर्य का विषय इसलिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस प्रारंभ से ही बलिदानियों की इस प्रकृति के औपनिवेशिक विरोध का कभी पक्षधर नहीं रही थी। चापेकर बंधुओं की शहादत से, भगत सिंह की शहादत तक, उसने स्वयं को असंबद्ध ही रखा। यहां पर उद्भूत करना आवश्यक है कि चापेकर बंधु के पक्ष में एकमात्र समकालीन समाचार पत्र शकाल्य के संपादक एसवी परांजपे ने चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखा, परिणामस्वरूप परांजपे को कांग्रेस के अधिवेशनों में आने से दादा भाई नौरेजी द्वारा रोक दिया गया। ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनके आधार पर यह समझा जा सकता है कि आखिर चौरी चौरा जनाक्रोश की प्रस्तुति इतिहास में सही अर्थों में नहीं की गई। इसके पश्चात प्रारंभ होता है चौरी चौरा का चतुर्थ समय खंड काल, वह इसलिए कि 172 लोग फांसी नहीं चढ़े, शहादत की यह संख्या 19 ही रह गई। सत्र न्यायालय के निर्णय उपरांत एक व्यक्ति जो इन जनों के समर्थन में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं वह हैं बाबा

राघवदास। मूलतरु महाराष्ट्र के निवासी और एक संत के रूप में पूर्वीचल द्वारा अपनाए गए। शायद यही भारतीयता का मूल तत्व है, आप कहां के हैं यह मायने नहीं, आपके कार्य एवं आप समाज के लिए समर्पित हैं तो भारतीय समाज आपको बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता है। बाबा राघवदास ने चौरी चौरा के सत्र अदालत के निर्णय का खुला विरोध किया एवं चंदा एकत्रित कर महामना से संपर्क कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद दाखिल कराया। महामना द्वारा चौरी चौरा का मुकदमा लड़ा गया और 172 जनों को हुई फांसी की सजा को 19 जनों में उच्च न्यायालय ने परिवर्तित किया। प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार से औपनिवेशिक तंत्र कार्य करता था और चौरी चौरा की घटना को लेकर बाबा राघवदास एवं महामना जैसे देशभक्त भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करके मौन रहते, जैसे अन्य के द्वारा की गई थी तो वस्तुतरु आज चौरी चौरा में इन बलिदानियों की सूची 19 की न होकर 172 की होती। इतिहास के इस सत्य और शायदव्य को चिन्हित कर पाना चौरी चौरा के संदर्भ में लगभग असंभव है। समझने की आवश्यकता है कि चौरी चौरा का कथानक किन स्तंभों पर खड़ा किया गया? उत्तर स्पष्ट है—अधिकाशतरु इस प्रकार की घटनाएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम में आंदोलन की मर्यादा को क्षीण करने वाली घटनाओं के रूप में दर्शाई गई हैं। क्या यह जलियांवाला बाग का प्रतिरोध नहीं था? क्या राष्ट्रीय आंदोलन का खंड काल जलियांवाला बाग से प्रारंभ हो चौरी चौरा तक एक नया अध्याय नहीं लिख रहा था? आवश्यकता है इतिहास के इस क्रम को जोड़कर देखने की। जलियांवाला बाग एक तथाकथित सुसंस्कृत राज्य का हत्याकांड था और चौरी चौरा उस तथाकथित सुसंस्कृत राज्य को प्रत्युत्तर। यदि 1922 की घटना न्यायिक और नैतिक अपराध की श्रेणी में मात्र इसलिए आती है कि यह अहिंसा के सिद्धांतों को एक सीमा के पश्चात अस्वीकार कर देती है, क्योंकि यहां राज्य अपनी बर्बरता का निरंतर परिचय देता रहता है।

यदि उच्च न्यायालय में महामना द्वारा किए गए तर्कों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो वह इसी तथ्य पर आधारित है कि स्वयंसेवक थाना जलाने अथवा हत्या के इरादे से नहीं आए थे अर्थात् घटना इरादतन नहीं थी और जो घटना घटी उस में तत्कालीन जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका कारक तत्व थी। इसके अतिरिक्त, यदि हिंसा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत था तो आजाद हिंद फौज के मुकदमे में भारतीयों के बचाव में वे लोग क्यों अत्यंत तत्पर हो गए जो हिंसा के प्रज्ञोर विरोधी थे और नेता जी की भूमिका एवं वैचारिकी से असहमत थे। उत्तर है देश का ज्वार और नेता जी एवं आजाद हिंद फौज की लोकप्रियता जोकि शीघ्र ही स्वतंत्र देश की राजनीतिक स्थितियों पर अपना प्रभाव छोड़ सकती थी। आवश्यकता है चौरी चौरा को उसके खंड कालों में समझा जाना, जिससे यह मात्र एक स्थानीय घटना न होकर, राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को परिवर्तित करने वाले एक अति महत्वपूर्ण घटना की तरह समझा जा सके। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि इस घटना के पश्चात कांग्रेस असहयोग के मुद्दे को लेकर लगभग दूसरी बार बंटवारे के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई थी। इस घटना पर कांग्रेस और महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया सर्वविदित है। इसके अतिरिक्त यदि समकालीन समाचार पत्र-पत्रिकाओं में चौरी चौरा की घटना पर प्रतिक्रिया देखी जाए तो वह भी घटना की आलोचना से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए शब्दयदय साप्ताहिक पत्र के 11 फरवरी, 1922 के अंक में शीर्षक दिया गया—खेदजनक और भीषण हत्याकांड—दो दारोगा और 15 कांस्टेबलों की हत्या। इसके अलावा—द लीडर्स ने अपने आठ फरवरी, 1922 के अंक में लिखा—हिंसा और आगजनी के तांडव के बीच भीड़ ने बेहद सुनियोजित तरीके से थाना पर हमला करते हए।



टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बनीं अनुपमा फेम रूपाली गांगुली

एजेंसी

टीवी धारावाहिक अनुपमा जब से शुरू हुआ है, यह टीआरपी की रेस में सबसे ऊपर रहा है। इसे सफल बनाने में अनुपमा बनीं अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। शो में अपने दमदार अभिनय के जरिए उन्होंने दर्शकों के बीच खुद को स्थापित कर दिया है। वह लोकप्रियता के रथ पर सवार हैं। अब खबर है कि रूपाली टीवी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई है।

एक सूत्र ने बताया, रूपाली ने 1.5 लाख रुपये प्रति दिन की फीस से शुरूआत की थी। अब वह अनुपमा के लिए प्रति दिन 3 लाख रुपये की

मोटी रकम ले रही है। इसी के साथ वह

टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक रेस बन गई है।

रूपाली ने इस मामले में कई लोकप्रिय युवा नामों को पछाड़ दिया है। उनकी फीस राम कपूर और रोनित बोस रेयंस से भी ज्यादा बताई जा रही है।

अनुपमा में रूपाली एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही है, जो अपने बच्चों और परिवार के लिए हर हड़ से गुजरने के लिए तैयार रहती है। उनके अलावा शो में सुधांशु पांडे,

मदलसा शर्मा और गौरव खन्ना जैसे कई कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसमें रूपाली और गौरव की कोमेंटरी को खूब पसंद किया जा रहा है। सूत्र के मुताबिक, गौरव रोजाना 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं। इन्होंने बिंग बॉस 1 में बतौर ही रकम सुधांशु को भी मिलती है।

अनुपमा आजकल हर किसी की पहली पसंद बनता जा रहा है। यह लंबे समय से टॉप पर बना हुआ है। रूपाली ने अनुपमा का किरदार ऐसे निभाया है कि फैस उन्हें अब अनुपमा के नाम से ही जानते लगे हैं। हालांकि, इस भूमिका के लिए वह पहली पसंद नहीं थीं। श्वेता तिवारी, मोना गौरी प्रधान, साक्षी तवं, मोना सिंह और जूह रसराम जैसी अभिनेत्रियों के नाम पर विचार करने के बाद अंत में यह रोल रूपाली की झोली में गिरा था।

रूपाली ने 2001 में

धारावाहिक सुकन्या से अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह संजो नी से लेकर काव्यांशि तक और सपना बाबूल का... विदाई जैसे कई धारावाहिकों में नजर आई। उन्होंने बिंग बॉस 1 में बतौर प्रतियोगी भाग लिया था। अनुपमा से पहले रूपाली को साराभाई वर्सें साराभाई में लीड रोल में देखा गया था। इस शो में उनके किरदार मानिशा साराभाई को दर्शकों ने खूब सराहा। हालांकि, अनुपमा उनके लिए मील का पथर साबित हुआ है।

रूपाली टीवी से पहले कई बॉलीयुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने साहेब से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। वह फिल्म अंगारा में मिथुन चक्रवर्ती के साथ दिख चुकी हैं। उस वक्त रूपाली 19 साल की थीं और मिथुन 45 के।



वेब सीरीज रंगबाज में दिखेंगी रनवे 34 की अभिनेत्री आकांक्षा सिंह

एजेंसी

अभिनेत्री आकांक्षा सिंह ने

हिन्दी और तेलुगु सिनेमा में

उन्होंने इससे पहले परमाणु

और तेरे बिन लादेन जैसी

सफल फिल्मों

में निर्देशन

किया है। केप ऑफ गुड

फिल्म्स, अबु दंतिया

एंटरटेनमेंट, लाइका

प्रोडक्शंस और अमेजन

प्राइम वीडियो द्वारा फिल्म

का निर्माण

किया गया है।

अक्षय फिल्म पृथ्वीराज

में मुख्य भूमिका में है। वह

फिल्म रक्षाबद्धन में भी दिखने

वाले हैं।

यह फिल्म बाई-बहने

के रिश्तों पर आधारित है।

फिल्म ओह माय गॉड 2 भी

अक्षय के खाते से जुड़ी है।

वह बेल बॉटम के निर्माता

जैकी भागनानी की दूसरी

फिल्म सिंड्रेला का भी हिस्सा है।

वह जल्द ही प्रियदर्शन

की एक फिल्म में भी नजर

आ रही है।

अक्षय के बच्चन और रक्ष्या

के देखा जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक,

आकांक्षा आगामी बैबीराज

में अपने अभिनय का

तड़का लगाएंगी।

सूत्र की मानें

तो आकांक्षा फिल्हाल इस

सीरीज की शूटिंग लखनऊ

में कर रही है।

इस बार उन्हें

बिल्कुल अलग किरदार

में देखा जाएगा।

इस सीरीज में उन्हें मुख्य

भूमिका में देखा जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक,

आकांक्षा आगामी बैबीराज

में अपने अभिनय का

तड़का लगाएंगी।

सूत्र की मानें

तो आकांक्षा फिल्हाल इस

सीरीज की शूटिंग लखनऊ

में कर रही है।

इस बार उन्हें

बिल्कुल अलग किरदार

में देखा जाएगा।

अक्षय रनवे

34 में नजर आएंगी।

इस फिल्म में उन्होंने अजय

की भूमिका में देखा जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक,

आकांक्षा आगामी बैबीराज

में अपने अभिनय का

तड़का लगाएंगी।

सूत्र की मानें

तो आकांक्षा फिल्हाल इस

सीरीज की शूटिंग लखनऊ

में कर रही है।

इस बार उन्हें

बिल्कुल अलग किरदार

में देखा जाएगा।

अक्षय रनवे

34 में नजर आएंगी।

इस फिल्म में उन्होंने अजय

की भूमिका में देखा जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक,

आकांक्षा आगामी बैबीराज

में अपने अभिनय का

तड़का लगाएंगी।

सूत्र की मानें

तो आकांक्षा फिल्हाल इस

सीरीज की शूटिंग लखनऊ

में कर रही है।

अक्षय रनवे

34 में नजर आएंगी।

इस फिल्म में उन्होंने अजय

की भूमिका में देखा जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक,

आकांक्षा आगामी बैबीराज

में अपने अभिनय का

तड़का लगाएंगी।

सूत्र की मानें

तो आकांक्षा फिल्हाल इस

सीरीज की शूटिंग लखनऊ

में कर रही है।